निगमायुक्त एवं मंडलायुक्त की 'कड़ी चेतावनी' के बावजूद सारे शहर में मामूली बारिश से जलभराव

फ़रीदाबाद (म.मो.) वीरवार की शाम को बड़ी उम्मीदों के बाद बादल बरसे। लोगों ने गर्मी से तो राहत पाई लेकिन सड़कों पर जलभराव व गलियों में कीचड़ भराव ने कुदरत के इस वरदान को अभिशाप में बदल दिया। कच्ची कॉलोनियों में तो जीवन नारकीय हो ही जाता है, हालत पॉश सेक्टरों की भी बिगड़ जाती है। सेक्टर 9 में डीसी मॉडल स्कूल के सामने वाली सड़क पर चार बूंद बरसते ही आधा फुट पानी खड़ा होना तय है। सेक्टर 16 ए स्थित नहर कॉलोनी वाले मंदिर के सामने तथा राजमार्ग से नेहरू कॉलेज की ओर आने वाली सड़क पर जलभराव के चलते पैदल चलना दूभर है। सेक्टर 21 स्थित पुलिस आयुक्त कार्यालय के सामने वाली सड़क पर अच्छा-खासा जलभराव है। सड़क का पानी कार्यालय परिसर के अन्दर तक घुसा हुआ है, वाहन तो आराम से परिसर में घुस सकते हैं लेकिन पैदल चलने वालों के लिये यह आफ़त है।

शहर भर में इसी तरह के सैंकड़ों स्थान हैं जहां से बरसाती पानी की निकासी का कोई जरिया नहीं है। यहां खड़ा पानी खुद-ब खुद जब सूखेगा तब सूखेगाा। दरअसल यह 'हूडा' व नगर निगम के 'काबिल' इन्जीनियरों की 'काबलियत' का एक बेहतरीन नमूना है जिसका प्रदर्शन इन्होंने सड़कों के निर्माण द्वारा किया है एक्शीयन व एसई बनने की चाह में दुबले हुए जा रहे इन इन्जीनियरों को सड़क की लेवलिंग करने तक का ज्ञान नहीं है। असल में इन्हें ऐसे ज्ञान की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये लोग तो केवल टेंडर पास करके ठेकेदार को ठेका दे देते हैं और

बिल पास करके अपना कमीशन वसूल लेते हैं। इसका इन्हें पूरा ज्ञान है इससे अधिक की जरूरत ये लोग समझते भी नहीं।

राजमार्ग पर अजरोंदा मोड़ जलभराव का स्थाई स्थान है। जलभराव के चलते यहां ट्रैफ़िक जाम लगता है जिसका असर पूरे नीलम फ़लाई ओवर तथा नीलम चौक तक पड़ता है। मुसीबत जब ज्यादा बढने लगती है तो नगर निगम के इन्जीनियर ट्रैक्टर सक्कर मशीन द्वारा टेंकर भर-भर कर पानी निकालते हैं। जाहिर है इन ट्रैक्टरों के मोटे-मोटे बिल भी बनेंगे जिन्हें पास करने में मोटा कमीशन मिलेगा। इसलिये इन अधिकारियों के लिये जलभराव लाभ का सौदा है।

शहर के भीतर नालों की सफ़ाई के नाम पर करोड़ों खर्च करने के बाद कौन सा नाला साफ़ हुआ, अभी तक पता नहीं चला। यह बारिश तो अभी ट्रेलर थी जब पूरी फ़िल्म चलेगी तब पता चलेगा नालों की हकीकत का। फ़िलहाल इनमें से दो नालों ने अपना जलवा दिखा ही दिया। एक नाले ने इतना पानी बाटा चौक पर भर दिया कि पूरा चौक जाम हो गया और दूसरे नाले ने ओल्ड फ़रीदाबाद मेट्रो स्टेशन के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग पर इतना पानी खड़ा कर दिया कि ट्रैफ़िक रेंग-रेंग कर चलने लगा। इसके परिणामस्वरूप बदरपुर से बाटा तक राजमार्ग पर जाम की सी स्थिति बनी रही जिसे सम्भालने में ट्रैफ़िक पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी।

पाठकों ने पिछले महीने के अंकों में पढा होगा कि नालों की सफ़ाई का मतलब केवल और केवल लूट कमाई रह गया है। 'मज़दूर मोर्चा' ने निगमायुक्त अनीता यादव के बयान, जलभराव होने की स्थिति में संबन्धित इंजीनियरों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी, पर चुटकी लेते हुए लिखा था कि कड़ी कार्यवाही का मतलब नालों की सफ़ाई के नाम पर मोटे-मोटे टेंडर व बिल पास करा कर लूट कमाई का इंतजाम किया जाय मोर्चा ने यह भी लिख दिया था कि इसकी पोल जुलाई के पहले हफ़्ते तक खुल जायेगी और यही हुआ भी। फ़रीदाबाद हो या गुड़गांवा निगमायुक्त हों या मंडलायुक्त सबका एक जैसा हाल है। पूरा साल नालों की सफ़ाई व जलभराव के रोक-थाम के नाम पर करोडों रुपये डकारते जाओ और अंत में जनता को डुबने के लिये छोड़ दो।

निगमायुक्त के आदेश की धज्जियां उड़ाते कर रहे पानी बर्बाद

फ़रीदाबाद (म.मो.) निगमायुक्त अनीता यादव ने अभी पिछले दिनों फ़र्मान जारी किया था कि कारें व घर के आंगन धोने पर पानी बर्बाद करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। वैसे यह आदेश कोई नया नहीं है लगभग हर निगमायुक्त ने यही आदेश दोहराये हैं। इसके बावजूद न तो कार धोने वाले कोई रुके और न ही रोज़ाना अपना आंगन धोने से कोई बाज़ आया। अधिकांश ऐसे काम सेक्टरों खासकर पॉश सेक्टरों में रहने वाले तथाकथित बड़े लोग करते हैं।

इनके खिलाफ़ प्रशासन सख्त कार्यवाही तो दूर मामूली कार्यवाही तक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। दरअसल प्रशासनिक अधिकारियों की, कोई कार्यवाही करने की न तो नीयत है और न ही इच्छाशक्ति। वे सोचते हैं कि केवल मीडिया के द्वारा 'सख्त कार्यवाही' की धमकी मात्र प्रचारित करने से सारा मसला हल हो जायेगा। लेकिन ऐसा है नहीं। असल में इस तरह की थोथी धमकियां देकर खुद प्रशासन एवं अधिकारी अपनी फ़जीहत कराते हैं। किसी भी अधिकारी को तक तब कोई आदेश नहीं देना चाहिये जब तक उसे यह विश्वास न हो जाये कि उसके आदेश की पालन होगी। समझदार अधिकारी केवल वही आदेश जारी करते हैं जिनकी पालना करा पाने में वे सक्षम होते हैं। इसलिये निगमायुक्त अनीता यादव को भी समझदार बनने का प्रयास तो करना ही चाहिये।

डॉक्टर्स डे पर हरियाणा सरकार की पाखंडी नौटंकी

फ़रीदाबाद (म.मो.) सन 1948 से 1962 तक बंगाल के मुख्यमंत्री रहते हुए मरीज़ों को देखने वाले डॉक्टर बीसी राय के जन्मदिन पहली जुलाई को डॉक्टर्स डे का दर्जा तो तीसियों वर्ष पहले मिल चुका था, परन्तु इसे मनाने की जरूरत हरियाणा सरकार को अब महसूस हुई। आगामी विधानसभा चुनाव के लिये भाजपा सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य व सुरक्षा का जुमला गढा है। जब धरातल पर कुछ न करना हो तो जुमलेबाज़ी पर आधारित नौटंकी से ही काम चलाया जाता है।

इसी उद्देश्य से भाजपा की खट्टर सरकार ने पहली जुलाई को राज्य के सभी ज़िलों में डॉक्टर्स डे की नौटंकी करने का फ़र्मान जारी किया। इसका मुख्य केन्द्र पंचकुला रखा गया जहां से मुख्यमंत्री खट्टर व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सभी ज़िलों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा सम्बोधित किया। घोषित तो यह किया गया था कि हर ज़िले से मुख्यमंत्री तथा स्वास्थ्यमंत्री संवाद यानी सवाल-जवाब करेंगे, लेकिन मामला इन दोनों के भाषण तक ही सीमित रहा।

भाषणों में स्वास्थ्य सम्बन्धी मूल समस्याओं-डॉक्टरों व स्टाफ़ सहित तमाम संसाधनों की कमी को लेकर कोई चर्चा तक नहीं की गयी, समाधान की तो बात ही क्या करनी थी। आये दिन मरीज़ों के हाथों पिटते डॉक्टरों की असल समस्या, डॉक्टरों व मरीज़ों के बढते अनुपात व बद से बद्तर होती जा रही चिकित्सा सेवाओं को दुरूस्त करने की बजाय डॉक्टरों की सुरक्षा के लिये लाठीधारी होम गार्ड देने की बात कही। सुरक्षा का यही उपाय बेहतरीन है तो खट्टर जी अपनी व अपने तमाम लगुए भगुओं को भी सशस्त्र गनमैन की जगह होम गार्ड ही क्यों नहीं लगाते? वैसे गनमैन और होम गार्ड अपने आप में सुरक्षा का कोई उपाय नहीं है। मंत्रियों ने डॉक्टरों को नसीहतें दी कि वे मरीज़ों से मीठा व्यवहार करें, प्यार से बात करें आदि-आदि। उन्होंने आरएमपी डॉक्टरों का उदाहरण देते हुए कहा कि वे अपने मौहल्लों में कितने लोकप्रिय होते थे, वे सब लोगों सें व्यक्तिगत रूप से जुड़े रहते थे। प्राइवेट डॉक्टारों को नसीहत परोसी गयी कि वे उनका मुफ़्त इलाज करें जो फ़ीस देने में असमर्थ हों। यानी खट्टर व उनकी सरकार ने फली नहीं फ़ोड़नी, जो कुच्छ करना है डॉक्टरों ने ही करना है, नेता तो केवल सत्ता की मलाई खाने व मौज-मस्ती करने को बने हैं। शायद इसी लिये इन मंत्रियों ने सवाल-जवाब से बचना चाहा क्योंकि सेवारत डॉक्टर्स तो पता नहीं कुछ पूछते या न पूछते लेकिन राज्य भर के तमाम मेडिकल कॉलेजों के छात्र अवश्य तीखे

प्रश्नों में इन्हें उलझा देते।

मुख्य अतिथि होने के लिये संघी होना जरूरी

राज्य सरकार की ओर से स्थानीय सिविल सर्जन गुलशन अरोड़ा व उपायुक्त द्वारा एनएच तीन स्थित मेडिकल कॉलेज में प्रायोजित इस नौटंकी के लिये सर्वोदय अस्पताल के डॉक्टर बालकृष्ण को आमंत्रित किया गया। डॉक्टर तो वे अन्य स्थानीय डॉक्टरों की तरह सामान्य ही हैं, परन्तु उनकी एक मात्र खूबी आरएसएस से जुड़ाव है। उन्हें यह सम्मान देकर सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि संघियों को हर जगह प्राथमिकता दी जाय।

डॉ. रमण कक्कड़ के बजाय डॉ. एनके पांडे को सम्मानित किया

कभी सरकारी नौकरी न करने के बावजूद सेक्टर 16 के रहने वाले डॉक्टर रमण कक्कड़ ने टीबी जैसी गंभीर महामारी के इलाज में जो प्रशंसनीय योगदान दिया उसको दरकिनार करते हुए जनता का खून निचोड़ने वाले एशियन अस्पतपल के मालिक डॉ. एनके पांडे को पंचकुला बुला कर मुख्यमंत्री खट्टर ने सम्मानित किया।

धन बचाने के चक्कर में, टीवी का राष्ट्रीय प्रोग्राम चलाने वाले विभाग ने सन् 2000 में मरीज़ को प्रति दिन दवा देने के बजाय एक दिन छोड़कर दवा देने का नियम बनाया। वर्ष 2004 तक डॉक्टर रमण को इसके दुष्परिणाम नज़र आने लगे तो उन्होंने राष्ट्रीय टीवी की नियंत्रण विभाग को इससे अवगत करा कर पुराने नियम पर आने का अनुरोध किया। विभाग नहीं माना तो डॉ. रमण ने दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। विभाग को नोटिस हुआ जवाब में विभाग ने डॉ. रमण के सुझाव को केवल अपनी मशहूड़ी फैलाने का स्टंट बताया। हाई कोर्ट ने डॉ. रमण से अपनी बात के पक्ष में सबूत मांगे।

सबूत जुटाने के लिये डॉ. रमण ने बीके अस्पताल से जुड़े टीबी अस्पताल में 2010 से 2013 तक काम किया। इस काम के दौरान उन्होंने तथ्यात्मक आंकड़े जुटाकार पुनः हाई कोर्ट में पेश किये। टीवी विभाग के पास इन तथ्यों को काटने के लिये कोई तर्क नहीं थे, लिहाज़ा दिल्ली हाई कोर्ट ने सन 2018 में विभाग को आदेश दिये कि वह डॉ. रमण के सुझाव अनुसार टीबी के मरीज़ों को एक दिन छोड़कर दवा देने की अपेक्षा लगातार दवाई खिलायें।

हरियाणा सरकार ने बेशक डॉ. कक्कड़ को सम्मान देने योग्य नहीं समझा लेकिन ज़िले की मेडिकल एसोशिएशन ने उन्हें सम्मानित किया। डॉ. रमण वास्तव में ही सम्मान एवं बधाई के पात्र हैं।

विकास हत्याकांड : शराब माफिया टंडन से जुड़ते तार

शराब की तस्करी व पुलिस की दलाली करने तथा गुंडा गिरोहों को पालने के लिये चर्चित तनेन्द्र टंडन को बीते सप्ताह में क्राइम ब्रांच वाले चार बार बुला चुके हैं। हर बार विधायक सीमा त्रिखा के फोन पर उसे छोड़ा जाता रहा है। अब छह जुलाई को उसे फिर से पुलिस ले गयी है। समझा जा रहा है कि कौशल गिरोह से उसके पुराने ताल्लुक हैं तथा वही आवश्यक सूचनायें एवं फिरौती वसूलने लायक लोगों के बारे में कौशल को बताता रहा है।

मजदूर मोर्चा ने इसके काले कारनामों के बारे में काफी विस्तार से वर्षों पहले प्रकाशित कर रखा है। एक बार तत्कालिक सीपी सुभाष यादव ने भी इसे उठवा लिया था तब भी सीमा त्रिखा इसे छुड़वाने खुद चलकर सुभाष यादव के पास गयी थी। अब देखना है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाती है।

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5
2. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड
3. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
4. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे
5. राम खिलावन बल्लबगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने
6. हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास
7. जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207